कमल संदेश
वर्ष 1, अंक 23 नई दिल्ली
18 मई 2020 (सायं 5 बजे)
दैनिक बुलेटिन
www.kamalsandesh.org

आर्थिक पैकेज से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा 17 मई को घोषित आर्थिक प्रोत्साहन की पांचवीं और आखिरी किस्त से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को मदद मिलेगी और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

- उन्होंने यह भी कहा कि इसके भारत के स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव होंगे।
- उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "राज्यों के विकास को भी इससे गति मिलेगी।"
- श्री मोदी ने कहा, "वित्त मंत्री द्वारा आज घोषित उपाय और सुधारों का हमारे स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव होगा।"
- उन्होंने कहा, "इनसे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को मदद मिलेगी और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।"

विपक्ष शासित राज्य प्रशासन ने अनुचित तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र आवाज़ों को निशाना बनाया: जेपी नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 18 मई को ट्विटर संदेशों की एक शृंखला में कहा, "पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया है कि विपक्षी शासित राज्यों में राज्य प्रशासन का सोशल मीडिया पर कोविड से निपटने हेतु स्थानीय सरकार की आलोचना के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र आवाज़ों को निशाना बनाने का गलत इस्तेमाल किया गया है। एक जीवंत लोकतंत्र में यह अस्वीकार्य है।"

- उन्होंने कहा, "अपनी असैद्धांतिक राजनीति के उजागर होने से भयग्रस्त लोगों का निशाना बन रहे हर भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाजपा आपके साथ खड़ी है। हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आपके अधिकार की रक्षा करेंगे और लोकतांत्रिक ढांचे में इन अत्याचारी ताकतों का विरोध करेंगे।"
- श्री नड्डा ने कहा, "सार्वजनिक जीवन में बहस और आलोचना की संस्कृति हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन आलोचना को दबाने के लिए राज्य एजेंसियों का उपयोग करना सत्ताधारी के लिए अशोभनीय है। जब उनकी असफलता पर सवाल उठाया जाता है, तो विपक्ष को राजनीतिक तर्कों का पालन करना चाहिए।"

लॉकडाउन 31 मई, 2020 तक बढ़ाया गया

24 मार्च, 2020 से ही लागू लॉकडाउन के उपायों से 'कोविड-19' के फैलाव को रोकने में काफी मदद मिली है। अत: इसे ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को 31 मई, 2020 तक और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 17 मई को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरे देश में कुछ गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी :

- केवल घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों अथवा गृह मंत्रालय द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई है उन्हें छोड़कर यात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं;
- मेट्रो रेल सेवाएं;
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान चलाना;
- बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में कैंटीन चलाने को छोड़कर होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं;
- सिनेमा, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला मनोरंजन पार्क;
- सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इसी तरह की अन्य सभाएं और अन्य बड़े समागम; और जनता की धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों तक पहुंच - पर रोक रहेगी।
- वहीं, रेस्तरां को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने की अनुमति होगी।
- संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आपसी सहमति से वाहनों और बसों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति दी गई है।

कमल संदेश

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में लगाए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते हैं : गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 17 मई 2020 को लॉकडाउन प्रतिबंधों के बारे में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। चूंकि लॉकडाउन को 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया, इसलिए प्रतिबंधों में व्यापक छूट दी गई।

- आज से प्रभावी नए दिशा-निर्देशों के तहत, अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही 17 मई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का परिसीमन या निर्धारण करेंगे।
- गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह हिदायत दी है कि संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत लॉकडाउन प्रतिबंधों में व्यापक छूट दिए जाने के बावजूद राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में लगाए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते हैं। यही नहीं, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान स्थिति के जमीनी स्तर के विश्लेषण के आधार पर आवश्यक समझने पर कुछ अन्य गतिविधियों या कार्यों को निषिद्ध कर सकते हैं या पाबंदियां लगा सकते हैं।

कमल संदेश

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत सात सेक्टरों में सरकारी सुधारों और सहायक उपायों की घोषणा

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 से लड़ने के लिए घोषित किए गए पैकेज पर 17 मई को आयोजित पांचवीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी सुधारों और समर्थन की दिशा में उठाए गए उपायों के 5वें और आखिरी हिस्से की घोषणा करते हुए कहा :

- रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के आवंटन में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी।
- 'पीएम ई-विद्या', डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा जल्द ही शुरू की जाएगी।
- आईबीसी से संबंधित उपायों के माध्यम से कारोबार में सुगमता और बेहतर होगी
- दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रु. किया गया।
- कंपनी कानून की मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर किया जाएगा।
- केन्द्र ने केवल वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार की सीमा 3% से बढ़ाकर 5% करने का फैसला किया है। इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे।

कमल संदेश

कोविड-19 से निपटने में टीडीबी ने प्रौद्योगिकियों को मंजूरी दी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सांविधिक निकाय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी), कोविड महामारी के रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, उद्यमियों और उद्योगपतियों के प्रयासों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है।

- टीडीबी ने व्यावसायीकरण के लिए छह परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें थर्मल स्कैनर, चिकित्सा उपकरण, मास्क और डायग्नोस्टिक किट शामिल हैं।
- कोकोसलैब्स इनोवेशन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक कम लागत वाले समाधान के व्यवसायीकरण की योजना बनाई है। इसके तहत भीड़ में असामान्य शरीर के तापमान वाले व्यक्तियों की पहचान की जायेगी और अधिकारियों को फोन और लैपटॉप पर सूचना/चेतावनी दी जायेगी।
- उत्पाद में मास्क के साथ और बिना मास्क वाले व्यक्ति का पता लगाना और उसे ट्रैक करना, उम्र, लिंग, तापमान और चेहरे की पहचान जैसी विशेषताएं शामिल हैं जो वास्तविक समय में कई लोगों की पहचान कर सकती हैं।
- टीडीबी ने लेटोम इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर को वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी। कंपनी ने डिजिटल डिस्प्ले के साथ बैटरी चालित पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों के व्यवसायीकरण की योजना बनाई है, जो आईसीयू और आइसोलेशन वार्डों के लिए उपयुक्त रेडियोग्राफी उपकरण है।

कमल संदेश

कोविड-19 पर अपडेट

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने लॉकडाउन 3.0 के आखिरी दिन कहा कि पिछले 14 दिन में मामलों के दोगुना होने की रफ्तार जहां 11.5 दिन थी, वहीं पिछले 3 दिन में यह बेहतर होकर 13.6 दिन हो गई है।
- मृत्यु दर घटकर 3.1% हो गई और रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 37.5% हो गई।
- (कल के आंकड़ों के अनुसार) कोविड-19 के रोगियों की संख्या आईसीयू में 3.1%, वेंटीलेटर पर 0.45% और ऑक्सीजन सपोर्ट पर 2.7 प्रतिशत है।
- देश में 17 मई 2020 तक कोरोना के कुल 90,927 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 34,109 लोग ठीक हो गए हैं और 2872 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई।
- पिछले 24 घंटे में 4987 नए मामलों की पुष्टि हुई है।
- स्वस्थ होने की दर बढ़कर 37.5% हो गई है और अब तक 22 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। (17 मई को जारी)

कमल संदेश

twitter

अपनी असैद्धांतिक राजनीति के उजागर होने से भयग्रस्त लोगों का निशाना बन रहे हर भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाजपा आपके साथ खड़ी है। हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आपके अधिकार की रक्षा करेंगे और लोकतांत्रिक ढांचे में इन अत्याचारी ताकतों का विरोध करेंगे।

@jpnadda

स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई सीमा अब 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। यह निर्णय 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से भारतीय रक्षा उत्पादन क्षमताओं की वास्तविक क्षमता को उजागर करेगा। ये घोषणाएं गेम चेंजर साबित होंगी।

@rajnathsingh

कल अहमदाबाद में 4900+ बैकलॉग संख्या (पिछली कुल संख्या) थी और आज मुम्बई में 5200+ बैकलॉग संख्या है जिसका आमतौर पर कोई उल्लेख नहीं करता है..घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। # इंडिया फाइट्स कोविड-19

@blsanthosh

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

नोवल कोरोनावायरस रोग (COVID-19)

Help us to help you

COVID-19 के मरीजों के प्रति भेदभाव और उत्पीड़न उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है

हमें मिलकर COVID-19 से लड़ना है

COVID-19 संबंधित जानकारी के लिए
राज्य हेल्पलाइन नंबरों या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के 24X7 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें
1075 (टोल फ्री), ई–मेल करें: ncov2019@gov.in , ncov2019@gmail.com

mohfw.gov.in | @MoHFWIndia | @MoHFW_INDIA | mohfwindia | @mohfwindia

आर्थिक योगदान हेतु अपील

खाता का नाम :
PM CARES
खाता संख्या :
2121PM20202
IFSC कोड :
SBIN0000691
Swift कोड :
SBININBB104
बैंक शाखा :
भारतीय स्टेट बैंक
नई दिल्ली मुख्य शाखा

Donate Now

Aarogya Setu
मैं सुरक्षित | हम सुरक्षित | भारत सुरक्षित

Download

COVID-19 INDIA

as on : 18 May 2020, 17:00 GMT+5:30

56316	36823	3029	1
Active Cases	Cured / Discharged	Deaths	Migrated

संपादकीय

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के विवरण सामने आने से देश में सुरक्षित भविष्य के प्रति आशा और विश्वास का एक वातावरण बना है। यह पैकेज स्वयं में इतना विस्तृत एवं सर्वसमावेशी है कि हर वर्ग की आवश्यकताओं का इसमें ध्यान रखा गया है और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की योजना इसमें समाहित है।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की। किसान, मजदूर, महिला जन-धन ख़ाताधारक, वरिष्ठ नागरिकों आदि को डीबीटी के माध्यम से नकद रुपया देकर समाज के इन कमजोर वर्गों की नकदी सम्बन्धी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास हुआ है, जिसकी पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। दाल, चना सहित नि:शुल्क खाद्यान्न आपूर्ति कर इस बंदी के दौर में गरीब से गरीब व्यक्ति की भोजन की समस्या हल की गयी है। अपने गांव लौट रहे प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखते हुए मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है जिससे उन्हें अपने घर पर ही रोजगार मिलने में सहायता होगी। ग्रामीण भारत पर केंद्रित कृषि एवं कृषि सम्बन्धी क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाओं, कृषि ऋण की उपलब्धता, किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार एवं अन्य कदमों से आने वाले दिनों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था निश्चित ही आत्मनिर्भर बनेगी।

महामारी के शुरू से ही मोदी सरकार ने समाज के अत्यंत कमजोर वर्गों के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। आज जब समाज का गरीब से गरीब व्यक्ति सरकार की उच्च प्राथमिकता में है, 'अंत्योदय' के सिद्धांत को इस चुनौती भरे समय में क्रियान्वित होते देखा जा सकता है।

- shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

कमल संदेश

संपादक: प्रभात झा, **कार्यकारी संपादक:** डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक: संजीव कुमार सिन्हा, राम नयन सिंह

कला संपादक: विकास सैनी, भोला राय

डिजिटल मीडिया: राजीव कुमार, विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण: सतीश कुमार

दूरभाष : 011-23381428 ई-मेल : mail.kamalsandesh@gmail.com